[Shri T. Basheer]

rice in tlie open market from the neighbouring States has come to a stop as these neighbouring States, namely, Tamil Nadu, Karnataka and Andhra Pradesh imposed restrictions on the movement of rice from those Statea to other States. Kerala is very badly affected by the present unprecedented drought. More than half of the villages are affected by this drought. This is also one of the factors for the situation becoming grave.

Sir, according to the rationing order of the State, allotment of rations is only 320 grammes of rice per adult per day and half of it per non-adult per day, Even for this, two lakh tonnes per month are required to be distributed through the public distribution system. That means the State's requirement for the year is 24 lakh tonnes. Never has the Government of India allotted rice as per this requirement. The Government of India had been allotting 1,35,000 tonnes per month but from January, 1982 it has even been reduced to 95.000 tonnes and sometimes even 90,000 tonnes per month. The House and the Government will appreciate that the Kerala State has a well-knit network of public distribution system. The State's rationing system is the best of its kind in the country. 1 appeal to the Government to take into consideration this aspect also in the allotment of rice to the State. So I would appeal to the Government, through you, Sir, that Keraia should be allotted at least 1,35,000 tonnes of rice per month to be supplied through ration shops. That is 70 per cent of the actual requirement. The Kerala State's Civil Supplies Corporation and the State Government have approached the Central Government for permission to purchase rice from the neighbouring surplus States. I would request the Government to give sanction to purchase rice from other States as required by the State of Kerala.

Thank you.

REFERENCE TO THE ALLEGED RETRENCHMENT OF ADIVASI AND HARIJAN EMPLOYEES AND APPOINTMENT OF NON-ADIVASIS AND NON-HAROANS IN CLASS HI AND CLASS IV POSTS IN BOOL

श्री अश्विनी कुमार (बिहार) : माननीय उपापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान केन्द्रीय सरकार के जो बड़े-बड़े संस्थान बिहार में चल रहे है, जहां पर आदिवासियों और हरिजनों को नौकरियां दिये जाने का प्रावधान है, क्लास 3 और 4 में स्थानीय व्यक्तियों को लिये जाने का प्रावधान है, उनके साथ इस तरह का पक्षपात हो रहा है और उनको नौकरियां न देकर उनके स्थान पर अधिकारियों के रिश्तेदारों को नौकरियां दी जा रही हैं, इसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्रीमन् 19 मार्च के दैनिक प्रदीप में यह समाचार छपा है कि बी० सी० सी० एल० के धनबाद कोयला खानों की इकाइयों आकाश किनारी, सिदरी, कनकनी, बांजुरा, गोधर खानों के अन्दर सेल्फ-रिटायरमेंट स्कीम के अन्तर्गत आदिवासी हरिजन मजदूर-मजदूरिनों को सेवा से मुक्त कराकर बड़ी संख्या में गैर आदि-वासी हरिजनों और बाहरी व्यक्तियों को रखा जा रहा है। अखबारों में उन के रिश्तेदारों की सूची छपी है, जिसमें से कुछ नाम मैं सरकार के ध्यान के लिये पढ़ देना चाहता हूं ।

श्रीमन्, हुंतो भुइनो नाम के हरिजन को हटाया गया, रिटायर किया गया है और उनके स्थान पर उनके दामाद चिन्ता हरण पांडे की नियुक्ति की गई। इसी प्रकार से छोटो मुनो मनुप्राइन को हटाकर उसके दामाद राजकुमार गोप जो वहां के सहायक मैनेजर के भाई हैं, को नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार से जितने वहां पर आफिसर्स हैं उनके भाइयों और बच्चों को हरिजनों के दामाद बनाकर हरिजनों को रिटायर कराकर उनके स्थान पर दामादों को लिया जा रहा है।...

श्री उपसभापति : इंटर कास्ट मैरिज की होगी।

श्री अश्विनी कुमार : इंटर कास्ट मैरिज नहीं की है। बिहार सरकार का 5 हजार रुपया भी लिया है। यह भी आपको जानकारी मैं दे सकता हूं कि जो रिटायर हो गये हैं वह 25 साल के हैं और उनके दामाद 38 साल के हैं। ये कुछ फैक्ट्स हैं जिनकी ओर मैं सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं। उसमें इंटक के नेताओं का भी हाथ है और ये सारी चीजें बी० सी० सी० एल० के अन्दर हो रही हैं। केवल इतना ही नहीं, बिहार में चलाये जा रहे कारखानों के लिये जिन लोगों की जमीन ली गई थी 20 साल पहले, जिसमें करार था कि उनको मुआवजा दिया जायेगा, आपको आश्चर्य होगा यह जानकर कि उन विस्थापितों को दर-दर भटक कर भी नौकरियां नहीं मिल रही हैं, क्लास 3 और 4 में भी वहां के आदिवासियों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं।

इसका परिणाम यह हो रहा है कि रांची के अन्दर केन्द्र की कोयला निकालने की योजना ठप्प पड़ी है। आदिवासी लोगों को कहते हैं कि उनको मुआवजा नहीं मिलेगा। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आदिवासी और हरिजनों के लिये जिनके मसीहा आप बनते हैं, उनके लिये कुछ कीजिये नहीं तो वहां परिस्थिति और खराब हो जायेगी।

REQUEST FOR STATEMENT BY GOVERNMENT ON THE ACHIEVEMENTS OF EXPEDITION OF INDIAN SCIENTISTS TO ANTARCTICA

SHRI MANUBHAI PATEL (Gujarat) : Sir, there is a very heartening news about the successful expedition by our scientists in the South Pole in the Antarctica area. Yesterday they safely arrived a team of 27 scientists. We do not know about their achievements there. It is realiy an event of pride for the whole country, and we should welcome the successful results of the expedition.

Sir, this is altogether a new area for us. When the explorations in the space are very costly and the explorations on the land are not yet complete, it should particularly be welcomed in this area which is no man's land, where our scientists have gone and covered a good portion of land for future experiments and they have been able to explore certain things, the result of which the Government